

विदेशी शोध निर्माता फर्मों द्वारा करोड़ों रुपयों की धनराशि का बाहर भेजा जाता

* 475 श्री आर० वी० बड़ें : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में शोधधिया बनाने वाली फर्मों द्वारा 1971-72 में कितने रुपये की धनराशि अपने देश को भेजी गई; और

(ख) इस प्रकार धन को बाहर जाने में रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हेमकान्त बरुआ) : (क) 1971-72 में 50 प्रतिशत से अधिक विदेश स्वामि व वाली विदेशी शोध निर्माता फर्मों द्वारा 525 लाख रुपये की राशि बाहर भेजी ।

(ख) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार भारतीय कर्षकों का भुगतान करने के बाद लाभ एवं लाभांशों की राशि प्रायः बाहर भिजवाई जा सकती है। तथापि 100 प्रतिशत विदेशी स्वामित्व की कंपनियों को लाभांश घोषित करने के लिए यदि आरक्षित सखि में से धन निकलवाना पड़े तो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को निम्न विषयों के बारे में संतुष्ट करना आवश्यक होगा :-

(i) कि आरक्षित निधि में से पिछले 5 वर्षों की औसत पर केवल लाभांश बनाए रखने के लिये अथवा प्रदत्त पूँजी के 10 प्रतिशत धर, इनमें से जो अधिक हो, निकाला गया है ।

(ii) कि आरक्षित निधि से निकाला गया धन कुल प्रदत्त पूँजी और वर्ष के आरम्भ में कंपनी की निवार्ध आरक्षित निधियों के 10% से अधिक नहीं है एवं

(iii) कि धन निकालने के बाद निवार्ध आरक्षित निधियों का बाकया उपरोक्त में क्वचित प्रदत्त पूँजी एवं आरक्षित निधियों के

15 प्रतिशत से कम नहीं रह जाता रायल्टी एवं तकनीक जानकारी की फीस हेतु धन बाहर ले जाने की रिजर्व बैंक के यह सल्लि कर लेने पर इजाजत दी जाती है कि भुगतान सरकार द्वारा मंजूर की गई शर्तों के अनुसार ही है ।

Diversion of Funds for Flood Protection Schemes for other Purposes

* 476. SHRI SARJOO PANDEY: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) whether funds allotted for flood protection schemes have been diverted to other schemes by some State Governments; and

(b) if so, what steps have been taken to see that funds allotted for flood control measures are not diverted for other purposes?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO): (a) and (b). Under the procedure evolved for the Fourth Plan, the Central assistance to the State Governments for their Plan schemes is provided in the shape of block loans and grants and is not tied to any particular projects or head of development. Thus there is no earmarked assistance for flood control schemes. The State Governments are free to allocate the funds to various heads of development according to priority.

However, the Government of India have provided special financial assistance for acceleration of flood control programme and priority schemes in some States and these amounts have been utilised for the purpose for which they were provided.